RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 20 MARCH TO 26 MARCH 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 26 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एक महीने में 800 कंपनियां दिवालिया... कनाडा का निकला दिवाला! Page 2

अमीर और गरीब के बीच का फासला ब्रिटिश राज से भी ज्यादा, रिकॉर्ड हाई पर 1 प्रतिशत रिच की दौलत Page 4

खिलौनों के खेल में कैसे भारत ने चीन को किया चित? यूं पावरहाउस बन रहा है अपना देश Page 5

editoria!

चीन की चुनौती

भारत और भारतीय सेना के लिए चीन एक प्रमुख रक्षा चुनौती है. देश के रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि चीन की यह चुनौती दोनों देशों के बीच अनिर्धारित सीमा तथा चीन के उभार के कारण हैं. उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्थायी सीमा के रूप में है. भारत और पाकिस्तान की सीमा का एक हिस्सा इसी तरह का है, जिसे नियंत्रण रेखा की संज्ञा दी जाती है. ऐसी रेखाएं सीमा विवादों के हल नहीं होने कारण स्थापित की गयी हैं. पचास के दशक में तिब्बत पर कब्जे के कारण चीन हमारा नया पड़ोसी बना और उससे पहले भारत विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया. इन दोनों के साथ सीमा विवाद भी हैं और युद्ध भी हो चुके हैं. हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में भारत और चीन के बीच समझौता है, पर चीन लगातार सैन्य घुसपैठ और जमावड़े के सहारे यथास्थिति को भंग करने की कोशिश करता रहा है. साल 2017 में दोक्लाम और 2020 में गलवान की घटनाएं उसके विस्तारवादी रवैये के उल्लेखनीय उदाहरण हैं. गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई चरणों की बातचीत हो चुकी है, पर चीन अपने सैन्य जमावड़े को हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है. कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर कहा था कि जब तक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी, तब तक तनाव बना रहेगा. रक्षा प्रमुख जनरल चौहान ने कहा है कि विवादित स्थानों पर यथास्थिति बदलने के चीनी सेना के प्रयासों का प्रतिकार जारी रहेगा. उन्होंने आगाह किया है कि जैसा विवादित सीमाओं के साथ हमेशा होता है, विरोधी नये तथ्य और तर्क गढ़ने का प्रयास करता है, हमारे पड़ोसी भी कर सकते हैं. उन्होंने आह्वान किया है कि विद्वानों, रणनीतिकारों, छात्रों, लोगों - सभी को ऐसी कोशिशों के बरक्स खड़ा होना होगा. हमारे दोनों आक्रामक पड़ोसी एक-दूसरे के बड़े करीब भी हैं और एक- दूसरे की गलतियों को भी सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं. इतना ही नहीं, वे भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक टिप्पणी करने के साथ-साथ हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर भी चोट करते हैं. हाल में चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा तथा वहां की परियोजनाओं पर चीन ने निराधार सवाल उठाया था. चीन और पाकिस्तान से संवाद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब तक दोनों देश मुख्य मुद्दों पर ईमानदारी एवं पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, संबंध बेहतर नहीं हो सकेंगे.

प्रति व्यक्ति आय में हो रहे ये बदलाव

RBI ने बताया तेजी से ग्रोथ के पीछे क्या है वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

मार्च 2024 के महीने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन के मुताबिक, प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। आरबीआई ने एमएमसीजी सेक्टर में संभावित नरमी और प्रति व्यक्ति आय वितरण में बदलाव के साथ इंडियन इकॉनमी के लिए बेहतर हो रही बातों पर रोशनी डाली है। स्टेट ऑफ इकॉनमी पर एक लेख में यह कहा गया है कि छोटे शहरों में अवसरों के कारण ग्रोथ हो रही है। सभी लाइफस्टाइल सेग्मेंट में बिजनेस ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्केट रिसर्च से संकेत मिलता है कि घरेलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर अगले छह महीनों में मॉडरेट ग्रोथ देख सकता है। दूसरी ओर, प्रीमियम कंज्यूमर बिजनेस के लिए डिमांड आउटलुक मजबूत है और ग्रोथ की लय मीडियम टर्म में बनी रहने की उम्मीद है। आरबीआई बुलेटिन में कहा गया है कि इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। हालांकि इंफ्लेशन को तेजी से घटाकर चार फीसदी तक लाने के भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य की दिखा में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बाधा बन रही हैं।

महंगाई बन रही बाधा

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित रिटेल महंगाई रिटेल महंगाई दिसंबर से घट रही है। फरवरी में यह 5.09 फीसदी थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई में एक टीम ने अपने लेख में कहा, भले ही डेडलाइन इंफ्लेशन में व्यापक नरमी के साथ महंगाई लगातार घट रही है, लेकिन खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों के दबाव के चलते इसे तेजी से चार फीसदी पर लाने में बाधा पैदा हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया गया है। अनुमान लगाया गया है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रह सकती है। इससे पहले फरवरी में पॉलिसी में आरबीआई ने इस अवधि के लिए अनुमान को 7 फीसदी पर रखा था।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इजाफा

चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.88 फीसदी बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है। बताया गया है कि 17 मार्च तक कुल कलेक्शन 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है, जिससे 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का सिक्युरिटी लेनदेन टैक्स भी शामिल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन

उद्योगपति सचिन बंसल सलाहकार समिति सदस्य बनें

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में इंदौर के उद्योगपति श्री सचिन बंसल अध्यक्ष इंडियन प्लास्ट पैक फोरम को विशेष रूप से सदस्य नामांकित किया गया है। मप्र शासन ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Plastic Waste Management Rules 2016) अंतर्गत बिन्दु क 16 के अनुसार प्लास्टिक एवं पैकेजिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन हुआ। जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय की अनुशंसा पर श्री सचिन बंसल को राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के विशेष सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ईपीआर देश के मुख्य वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। श्री बंसल प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एक्सपर्ट होने के साथ ही औद्योगिक संगठन इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष और भास्कर रेजिन्स प्रा.लि, बसल पॉलिमर के एमडी एवं सीईओ है। श्री सचिन बंसल के प्लास्टिक उद्योग के लंबे अनुभव से इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान और फायदा मिलेगा। इस राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के गठन का उद्देश्य राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management) के लिए राज्य स्तरीय नीतियां और योजनाएं बनाना। प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है। समिति का उद्देश्य राज्य स्तरीय रणनीति तैयार करना, प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए योजनाएं बनाने और प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना के लिए काम करेगी। समिति के सदस्य के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और प्लास्टिक उद्योग के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

श्री सचिन बंसल

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बंपर बढ़ोतरी, 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ पर पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 19.88 फीसदी बढ़ा है। यह बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है। इसमें 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) भी शामिल है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक करीब 3.37 लाख करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया जा चुका है। सकल आधार पर रिफंड समायोजन से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये था। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.74 फीसदी ज्यादा है।

सीबीडीटी ने क्या कहा है?

सीबीडीटी ने कहा, 'वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अस्थायी आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध टैक्स संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,76,776 करोड़ रुपये था। यह वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 19.88 फीसदी अधिक है।' सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह के संशोधित अनुमान में पूरे वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियां 19.45 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद जताई है।

एक महीने में 800 कंपनियां दिवालिया...

कनाडा का निकला दिवाला!

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस समय मंदी की चपेट में हैं। जापान बाल-बाल इससे बचा है लेकिन अब कनाडा के मंदी में फंसने का खतरा पैदा हो गया है। देश में बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करने वाली कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। केवल जनवरी में ही 800 से अधिक कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया। इससे पहले 2023 में देश में बैंकरप्सी फाइलिंग में करीब 40 फीसदी की तेजी देखने को मिली। अभी जितनी कंपनियां बैंकरप्सी के लिए आवेदन कर रही हैं, वह संख्या 13 साल में सबसे ज्यादा है। कोरोना काल के दौरान कंपनियों को 45,000 डॉलर का ब्याज मुक्त लोन दिया गया था जिसे चुकाने की डेडलाइन जनवरी में खत्म हुई थी। कनाडा की जीडीपी में छोटी कंपनियों की करीब 33 फीसदी हिस्सेदारी है। सवाल उठ रहा है कि क्या कनाडा मंदी की तरफ बढ़ रहा है?

कनाडा के सरकारी आंकड़ों की मानें तो देश की इकॉनमी मजबूत बनी हुई है। लेकिन छोटी कंपनियों और कई कंज्यूमर्स को संघर्ष करना पड़ रहा है। दिसंबर में कनाडा की इकॉनमी के 0.3 फीसदी बढ़ने की संभावना है। इस तरह चौथी तिमाही में इसमें 1.2 फीसदी की तेजी की संभावना है। तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी में 1.1 फीसदी गिरावट रही थी। लगातार दो तिमाहियों में गिरावट को मंदी कहा जाता है। इस तरह देखें तो कनाडा फिलहाल मंदी की चपेट में आने से बच गया है। लेकिन जनवरी में जिस तरह से एक के बाद एक 800 कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया, उससे एक बार फिर मंदी की आशंका सिर उठाने लगी है।

भारत से लिया था पंगा

कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल भारत से पंगा लिया था। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों देशों ने ही एक-दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया था। दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 देशों के सम्मेलन से ही हो गई थी। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रूडो की बैठक हुई थी। इसमें मोदी से ट्रूडो से कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा था।

जी-20 के बाद दो दिन को ट्रूडो भारत में ही रहे थे। विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के चलते उन्हें भारत में रहना पड़ा था। कनाडा लौटने पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। अपने देश लौटते ही ट्रूडो आक्रमक दिखें। उन्होंने भारत पर कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी भारत ने हत्या करवाई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था।

कितने देश हैं मंदी में

इस समय ब्रिटेन समेत दुनिया के आठ देश मंदी में फंसे हैं। इनमें ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, लक्जमबर्ग, मोल्दोवा, पेरू और आयरलैंड शामिल हैं। दिलचस्प बात है कि इनमें से छह देश यूरोप के हैं। इस लिस्ट में अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का कोई देश नहीं है। जापान मंदी से बाल-बाल बचा है। कई और देशों पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इनमें जर्मनी भी शामिल है। यूरोप की यह सबसे बड़ी इकॉनमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। चीन में हालात भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका पर भी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और यह जीडीपी का 125 परसेंट से अधिक पहुंच चुका है।

पीवीआर आइनॉक्स का पॉकेट-फ्रैंडली पासपोर्ट अब बेमिसाल फीचर्स के साथ पूरे भारत में उपलब्ध है

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स लि. ने अपनी मंथली सिनेमा सब्सक्रिप्शन सर्विस 'पासपोर्ट' का दूसरा एडिशन लॉन्च किया है। इसे कंज्यूमर का कीमती फीडबैक लेकर दोबारा डिजाइन किया गया है। पासपोर्ट अब दक्षिण भारतीय राज्यों समेत पूरे देश में उपलब्ध है। और उसका यह दोहराव यूजर के लिये ज्यादा अनुकूल है। इसमें रोमांचक नये फीचर्स और कुछ शर्तें भी हैं। इसकी शुरूआत 18 मार्च से हो रही है और इसके साथ सब्सक्राइबर्स किफायती दामों पर फिल्में देख सकेंगे। सोमवार से गुरुवार तक सब्सक्राइबर्स सिर्फ 349 रूपये में हर महीने 4 फिल्में देख सकते हैं। पासपोर्ट के माध्यम से सब्सक्राइबर्स किसी और के लिये भी टिकट खरीद सकेंगे और रिडीम कर पाएंगे। अगर सब्सक्राइबर्स रिक्लाइनर्स पर या आइमैक्स, पी (एक्सएल), आईसीई, स्क्रीनएक्स, एमएक्स4डी या 4डीएक्स जैसे प्रीमियम और एक्सपीरियेंशियल फॉर्मेट्स में फिल्में देखना चाहते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट कूपन के ऊपर 150 रूपये की अतिरिक्त फीस देनी होगी। फिर उनका अनुभव ज्यादा मजेदार बन जाएगा। हालांकि यह फीचर दक्षिण भारतीय बाजारों में उपलब्ध नहीं होगा। फिल्मों के शौकीन पीवीआर एण्ड आइनॉक्स ऐप या वेबसाइट पर या पेटीएम के माध्यम से अपना पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट 2.0 ले सकते हैं। सब?सक्राइबर्स अग्रिम तौर पर 1047 रूपये का भुगतान कर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। इसमें उन्हें 350 रूपये के फूड वाउचर्स मिलेंगे। अभी सिर्फ 50,000 पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट्स, सिर्फ तीन हफ्ते तक उपलब्ध हैं। इसलिये फिल्मों के प्रेमी लोगों को सिनेमा के शानदार सफर के लिये जल्दी से जल्दी अपने-अपने पासपोर्ट्स पा लेने चाहिये।

पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट 2.0 के लॉन्च पर अपना रोमांच व्यक्त करते हुए, पीवीआर आइनॉक्स लि. के को-सीईओ गौतम दत्ता ने कहा, "पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट के पहले एडिशन को फिल्म देखने वालों से काफी प्यार और तारीफ मिली थी। लेकिन यूजर्स ने मायने रखने वाले कई फीडबैक भी दिये कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और देश में सिनेमा देखने के लिये जाने का अनुभव समृद्ध बनाने के लिये पासपोर्ट की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं।

तूफानी तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था, मॉर्गन स्टेनली ने भी माना लोहा, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। एजेंसी

निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003-07 जैसी लग रही है। उस समय आर्थिक वृद्धि दर औसतन आठ प्रतिशत से अधिक थी। मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही है। मॉर्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट 'द व्यूपॉइंटः इंडिया - व्हाई दिस फील लाइक 2003-07' में कहा कि एक दशक तक जीडीपी के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ''हमें लगता है कि पूंजीगत व्यय चक्र के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसलिए वर्तमान तेजी 2003-07 के समान है।''

इस वजह से आई तेजी

मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वर्तमान तेजी खपत की तुलना में निवेश बढ़ने के चलते है। शुरुआत में इसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से समर्थन मिला, लेकिन निजी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हो रही है। इसी तरह खपत को पहले शहरी उपभोक्ताओं ने सहारा दिया और बाद में ग्रामीण मांग भी बढ़ी। वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने और व्यापक आर्थिक स्थिरता से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है।

जीडीपी में आएगी और तेजी

रिपोर्ट में कहा गया है, ''हमारा मानना है कि मौजूदा तेजी जीडीपी के मुकाबले निवेश बढ़ने के चलते है। इसी तरह के वृद्धि चक्र में 2003-07 के दौरान जीडीपी के मुकाबले निवेश 27 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया था।''

जीडीपी के मुकाबले निवेश 2011 तक अपने उच्चस्तर पर था, जिसके बाद इसमें गिरावट आई। यह गिरावट 2011 से 2021 तक देखने को मिली, हालांकि उसके बाद स्थिति बदलने लगी और अब जीडीपी के मुकाबले निवेश 34 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2026-27 तक इसके 36 प्रतिशत होने का अनुमान है।

अपने दूध में इंसुलिन बना रही ये खास गाय, डायबिटीज मरीजों की आ सकती है मौज!

एजेंसी

वैज्ञानिकों ने डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इलिनोइस यूनिवर्सिटी (अर्बन-शैंपेन) के पशु वैज्ञानिक मैट व्हीलर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी जेनेटिकली मोडिफाइड गाय तैयार की है, जिसके दूध में मानव इंसुलिन पाया गया है। यह शोध, जो बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित (Ref) हुआ है, वैश्विक स्तर पर इंसुलिन की आपूर्ति की चुनौती के लिए एक संभावित समाधान प्रदान करता है। अभी तक, डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन मुख्य रूप से आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया या खमीर का उपयोग करके बनाया जाता है। यह नया तरीका, अगर सफल साबित होता है, तो इंसुलिन उत्पादन में क्रांति ला सकता है।

कैसे हुआ शोध

शोधकर्ताओं ने गाय के भ्रूणों में प्रोइंसुलिन (इंसुलिन का अग्रदूत) के निर्माण के लिए जरूरी विशिष्ट मानव डीएनए कोड डाला। इसके बाद इन भ्रूणों को सामान्य गायों में प्रत्यारोपित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वस्थ बछड़े का जन्म हुआ। हालांकि, इस गाय को प्राकृतिक रूप से गर्भवती कराने का प्रयास असफल रहा, लेकिन वैज्ञानिक दूध उत्पादन को प्रेरित करने में सफल रहे।

गाय के दूध में मिला इंसुलिन

दूध के विश्लेषण में पाया गया कि उसमें मानव प्रोइंसुलिन और इंसुलिन के समान आणविक भार वाले प्रोटीन मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, शोध से यह भी संकेत मिलता है कि गाय का दूध प्रोइंसुलिन को इंसुलिन में भी परिवर्तित कर सकता है। हालांकि अभी उत्पादन का स्तर कम है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक में बड़े पैमाने पर उत्पादन की काफी संभावना है।

ट्रांसजेनिक गायों के दूध में मिला प्रोटीन

अध्ययन के लेखकों के अनुसार, ट्रांसजेनिक गायों के दूध में पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन एक रोमांचक प्रणाली है। दूध में मौजूद प्रोटीएज (प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम) इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये प्रोटीएज प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं और पुनः संयोजित प्रोटीन को कार्यात्मक प्रोटीन में बदल सकते हैं। वहीं, कुछ दूध प्रोटीएज पुनः संयोजित प्रोटीन को नष्ट भी कर सकते हैं। यह शोध दुनिया भर में डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन की आपूर्ति को स्थिर और संभावित रूप से अधिक किफायती बनाने के लिए एक नया रास्ता खोलता है।

इंसुलिन क्या है?

इंसुलिन एक तरह का हॉर्मोन है जो हमारे शरीर में अग्नाशय (पैंक्रियाज) नाम के अंग द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर में रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। आसान शब्दों में कहें तो, हम जो भी खाते-पीते हैं उसमें से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से ग्लूकोज (रक्त शर्करा) से प्राप्त होती है। भोजन पचाने के बाद ग्लूकोज हमारे रक्तप्रवाह में मिल जाता है। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को संकेत देता है कि वे ग्लूकोज को अवशोषित कर लें, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है।

इंसुलिन नहीं बनने से क्या होता है

अगर शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, तो यह स्थिति डायबिटीज कहलाती है। डायबिटीज की स्थिति में ब्लड शुगर लेवल लगातार ऊंचा रह सकता है, जिससे शरीर को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

शराब के विज्ञापनों पर और सख्ती की तैयारी, सरकार ने मांगा डेटा, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने शराब के ब्रांडों द्वारा फर्जी विज्ञापनों (Surrogate Advertising) के कई मामले सामने आने के बाद, कंपनियों को विज्ञापन नियमों का उल्लंघन न करने के लिए आदेश दिया है। सीसीपीए ने कंपनियों से पिछले तीन सालों में शराब के साथ बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों (जिनको ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं) की लिस्ट देने को कहा है। साथ ही सीसीपीए ने पिछले तीन सालों में शराब और ब्रांड एक्सटेंशन उत्पादों (मिनरल वॉटर, ताश के पत्ते, म्यूजिक सीडी) की बिक्री से जुड़ा हुआ रेवेन्यू और टर्नओवर डाटा भी मांगा है। इसके अलावा सीसीपीए पिछले तीन सालों में हुए ब्रांड एक्सटेंशन के प्रमोशन पर हुए खर्च का विवरण भी मांग रहा है, जिसमें इवेंट स्पॉन्सरशिप, अवॉर्ड सेरेमनी, म्यूजिक फेस्टिवल, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया प्रभावितों को किए गए पेमेंट और टीवी विज्ञापन शामिल हैं।

जारी किए ये निर्देश

सीसीपीए के चीफ कमिश्नर रोहित कुमार सिंह ने जारी किए गए निर्देश में कहा, 'यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि ब्रांड एक्सटेंशन उत्पादों की वास्तविक बिक्री और उनके प्रचार पर खर्च किए गए धन के बीच कोई संबंध है या नहीं। यह आकलन यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या ब्रांड एक्सटेंशन उत्पादों का प्रचार वास्तव में विस्तारित उत्पाद को दर्शाता है या शराब के विज्ञापन के विकल्प के रूप में काम करता है।'

शराब के विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जिसके चलते कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए फर्जी विज्ञापन का सहारा लेती हैं। सीसीपीए का यह आदेश आईपीएल के लॉन्च होने के कुछ दिन पहले आया है, जब इस तरह के विज्ञापन अक्सर प्रसारित किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी चलाए जाते हैं।

उपभोक्ता अधिकारों के लिए खतरा

दो-पन्ने के निर्देश में कहा गया है कि, 'उद्योग को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सभी ब्रांड एक्सटेंशन विज्ञापन केवल वास्तविक विस्तार को ही दिखाए (अर्थात विज्ञापन पर होने वाले खर्च का अनुपात बिक्री और वितरण के अनुपात में होना चाहिए), और यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापनों में प्रतिबंधित श्रेणी के किसी भी तरह के संकेत न हों, जैसे कि टैगलाइन और लेआउट, और विज्ञापित किए जा रहे एक्सटेंशन के कैटेगरी के नाम को दबाया न जाए।' इसने यह भी कहा कि फर्जी विज्ञापन उपभोक्ता अधिकारों के लिए खतरा हैं।

अमीर और गरीब के बीच का फासला ब्रिटिश राज से भी ज्यादा, रिकॉर्ड हाई पर 1 प्रतिशत रिच की दौलत

एजेंसी

देश के टॉप अमीरों की संपत्ति रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से टॉप के एक फीसदी अमीरों की इनकम में 22.6 फीसदी और वेल्थ में 40.1 फीसदी हिस्सेदारी है जो रिकॉर्ड हाई लेवल है। इस मामले में भारतीय अमीरों ने अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी पछाड़ दिया है। यह खुलासा वर्ल्ड इनइक्लिलिटी लैब के पेपर से हुआ है। इस पेपर को नितिन कुमार भारती, लुकस चांसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची जैसे दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है। इस पेपर बिलेनियर राज (Billionaire Raj) में दावा किया गया है कि ब्रिटिश राज की तुलना में अब अधिक असमानता है।

बिलेनियर राज रिपोर्ट के मुताबिक इस समय अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक है। आजादी के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक इनकम और वेल्थ गैप में गिरावट दिखी थी लेकिन इसके बाद यह बढ़ना शुरू हुआ और 2000 के दशक की शुरुआत से आसमान छूने लगा। हालांकि वेल्थ के स्तर पर बात करें तो 2014-15 और 2022-23 के बीच यह गैप और तेजी से बढ़ा।

नीचे के 50 प्रतिशत के पास सिर्फ 15 फीसदी दौलत

पेपर के मुताबिक देश का औसत इनकम लेवल 1960 और 2022 के बीच सालाना 2.6 फीसदी की औसत दर से बढ़ा। 1960 और 1990 के बीच देश की रीयल ग्रोथ रेट 1.6 फीसदी सालाना थी जबकि 1990 से 2022 के बीच यह सालाना 3.6 फीसदी की दर से बढ़ी। अमीरों के दौलत की बात करें तो टॉप 10 फीसदी अमीरों के इनकम की हिस्सेदारी आजादी के समय में 40 फीसदी से घटकर 1982 में 30 फीसदी पर आ गई थी। हालांकि अब 2022 में यह बढ़कर 60 फीसदी पर पहुंच चुकी है। नीचे के 50 फीसदी लोगों के 15 फीसदी ही है।

अलग-अलग इनकम ग्रुप में काफी असमानताएं हैं। टॉप के 1 फीसदी अमीरों के पास औसतन 5.4 करोड़ रुपये की दौलत है जो औसतन भारतीयों की दौलत से करीब 40 गुना ज्यादा है। वहीं नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास औसतन 1.7 लाख और बीचे के 40 फीसदी लोगों के पास 9.6 लाख की औसतन दौलत है।

गैप ऐसे कम करने का दावा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्वीकरण का फायदा सिर्फ अमीरों की बजाय आम भारतीयों को भी मिले, इसके लिए जरूरी है कि इनकम और वेल्थ को लेकर टैक्स ढांचे को नए रूप में लाया जाए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर बड़े पैमाने पर सरकार निवेश करे। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 167 सबसे अमीर परिवारों पर अगर 2 फीसदी का सुपर टैक्स लगाया जाता तो इससे नेशनल इनकम का 0.5 फीसदी रेवेन्यू में मिलता जिससे न सिर्फ असमानता से लड़ने में मदद मिलती बल्कि सरकार के पास निवेश के लिए पूंजी भी आती।

निहार शांति पाठशाला फनवाला लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम

6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी बदली 80 हजार सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख से ज्यादा टीचर्स का कौशल बढ़ाया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एक देश के रूप में, हमने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें ग्रामीण भारत भी शामिल है। शिक्षा किसी भी समाज में प्रगति का प्रमुख अभिप्रेरक है और इस उद्देश्य को साझा करने वाले एक ब्रांड के रूप में, निहार नैचुरल्स शांति बादाम आंवला ने शिक्षा कौशल को योगदान करने के एक तरीके के रूप में पहचाना है। शिक्षा के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देने के ब्रांड के उद्देश्य के बारे में बताते हुये, सोमाश्री बोस अवस्थी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैरिको लिमिटेड ने कहा, ''निहार नैचुरल्स शांति बादाम आंवला हेयर ऑयल ने ब्रांड के उद्देश्य को पहचानने वाले ग्राहकों के साथ जो जुड़ाव बनाया है, उस पर हमें बहुत गर्व है। वर्ष 2019 में, निहार शांति पाठशाला फनवाला की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टूडेंट्स के बीच पढ़ने एवं समझने की काबिलियत को विकसित करने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ की गई थी। हमने अपने अनूठे इंग्लिश लिट्रेसी प्रोग्राम की पेशकश के साथ इस उद्देश्य को पूरा किया। यह शिक्षकों को एक ऐसी भाषा में साक्षरता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है, जो उच्च शिक्षा के बेहतर अवसरों के द्वार खोलती है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव को देखना वाकई में संतोषप्रद रहा है। अकेले 2023 में, ब्रांड ने 1.4 लाख सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी की और 2 लाख शिक्षकों को सफलतापूर्वक शिक्षित किया। इस तरह इससे भारत के हिंदी भाषी राज?यों के 142 जिलों में 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुये हैं। देश भर में निहार परिवार के हमारे ग्राहकों की मदद से, हमें आने वाले वर्षों में इस अभियान को और भी बेहतर और बड़ा बनाने की उम्मीद है।''

भारत का पहला रोबोट डॉग: सेना और पुलिस के लिए खुफिया जानकारी में मदद करेगा

IIT कानपुर ने किया तैयार

कानपुर । आईपीटी नेटवर्क

कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार जानवर कहा जाता है। इसीलिए लोग अपने घरों में कुत्तों को पालते हैं ताकि वह उनके घर की निगरानी रखें और किसी बाहरी के घर में घुसने पर उनको अलर्ट भी करें। इसी तरीके से कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जाता है। सेनाओं द्वारा किया जाता है क्योंकि यह खुफिया जानकारी निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। वहीं अब आईआईटी कानपुर ने भी देश का पहला रोबोट डॉग तैयार किया है जो पुलिस फोर्सज और सिक्योरिटी के लिए बेहद मददगार साबित होगा।

आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी एक्स्ट्रा रोबोटिक ने यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस रोबोट डॉग तैयार किया है जो दिखने में एक कुत्ते की तरीका है और यह इंसानी दिमाग से भी तेज काम करता है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको तैयार किया गया है। जहां पर कोई खुफिया जानकारी निकालनी हो जहां पर आसानी से इंसान ना पहुंच सके वहां के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं गंभीर मामलों में पुलिस की मदद करने का भी यह काम करेगा. साथ ही बड़ी घटनाओं का खुलासा करने में भी इसकी मदद ली जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है आधारित

आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले उदयपुर निवासी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 2019 में उन्होंने आईआईटी कानपुर में अपनी एक कंपनी इनक्यूबेटर की थी, जिसका नाम एक्स्ट्रा रोबोटिक रखा था, जिसके बाद उन्होंने देश का पहला रोबोट डॉग बनाने का प्लान किया था। इसके बाद एक डॉग को बनाया गया है यह डॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है। यह किसी भी जगह जाकर वहां की पल-पल की और खुफिया जानकारी निकालने में एक्सपर्ट है. उन्होंने बताया कि यह भारत का निर्मित पहला रोबोट डॉग है।

सेना और पुलिस के लिए करेगा सिक्योरिटी का काम

अभी सेना और पुलिस दोनों द्वारा सिक्योरिटी डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे-जैसे तकनीक बदल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है तो अब यह रोबोट डॉग्स भी सेना और पुलिस के मददगार साबित होंगे। यह खुफिया जानकारी निकालने से लेकर पल-पल की अपडेट देने का काम करेगा।

खिलौनों के खेल में कैसे भारत ने चीन को किया चित? यूं पावरहाउस बन रहा है अपना देश

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय खिलौनों की दुनियाभर में धूम मच रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2023 के बीच भारत से खिलौनों के निर्यात में 239 फीसदी तेजी आई है। इस दौरान आयात में 52 फीसदी गिरावट आई है। इसके साथ ही खिलौनों को ग्लोबल मार्केट में चीन का दबदबा कम हो रहा है और भारत नेट एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। दुनिया की कई बड़ी खिलौना कंपनियां अब चीन के बजाय भारत से खिलौने खरीद रही हैं। मार्केट रिसर्च फर्म ध्ध्ँ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टॉय इंडस्ट्री की वैल्यू पिछले साल 1.7 अरब डॉलर थी जिसके 2032 तक 4.4 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनकी बदौलत भारत आज इस इंडस्ट्री में पावरहाउस बन रहा है।

मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में खिलौनों की बिक्री के लिए बीआईएस अप्रूवल को अनिवार्य बनाने, देसी खिलौनों को बढ़ावा देने, दुनियाभर की कंपनियों की चाइना-प्लस-वन पॉलिसी और बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाकर 70 फीसदी किए जाने से देश में खिलौना उद्योग ने उड़ान भरी है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है

कि HaWro, Mattel, Spin Master और Early Learning Centre जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भारत से खिलौने खरीद रहे हैं। इसी तरह Dream Plast, Microplast और Incas चीन से भारत में अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं। बीआईएस की अनिवार्यता लागू होने से पहले भारत में 80 फीसदी खिलौने चीन से आते थे लेकिन अब चीन से खिलौनों के आयात में काफी कमी आई है।

दुनिया में बढ़ रहा दबदबा

टायर बनाने वाली चेन्नई की कंपनी एमआरएफ के पास भी एक टॉय ब्रांड है जिसका नाम इल्हेव्ददत है। कंपनी के सीईओ आर जसवंत ने कहा कि चीन के खिलौनों को बीआईएस से मान्यता नहीं मिली है। चीन से होने वाले आयात की जगह अब भारतीय प्रॉडक्ट्स ने ले ली है। दस साल पहले शायद ही कोई कंपनी भारत से खिलौने खरीद रही थी। लेकिन अब कई कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया है। इल्हेव्ददत कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को सप्लाई करती है जिनमें HaWro, Spin Master, Early Learning Centre, Flair और Drumond Park Games शामिल हैं। इस कंपनी के 60 फीसदी खिलौने एक्सपोर्ट होते हैं। Funskool दुनिया के 33 देशों को एक्सपोर्ट करती है जिनमें गल्फ देश, यूरोप और अमेरिका शामिल है।

आरपी एसोसिएट्स के मालिक पवन गुप्ता ने कहा कि भारत में खिलौनों का उत्पादन बढ़ गया है और कई कंपनियों ने भारत में अपना बेस बनाया है। पहले चीन से खिलौने खरीद रही कई कंपनियां अब दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इस लिस्ट में Microplast, Dream Plast और Incas जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। HaWro और Mattel जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत से खरीद कर रही हैं। भारत सरकार ने एक जनवरी, 2021 से उन खिलौनों के आयात पर रोक लगा दी थी जिन्हें बीआईएस से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साथ ही सरकार ने फरवरी 2020 में खिलौनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी थी जिसे मार्च 2023 में बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया था।

गुजरात बन रहा हब

टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए बीआईएस नियमों में और ढील देने की जरूरत है। एसोसिएशन का कहना है कि देश में 6,000 से अधिक खिलौना बनाने वाली यूनिट्स हैं जिनमें से केवल 1,500 के पास ही बीआईएस लाइसेंस है। एसोसिएशन के प्रेजिडेंट अजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने पिछले दो साल में एमएसएमई सेक्टर में कई तरह की छूट दी हैं। देश में कई स्टार्टअप कंपनियां इस सेक्टर में आगे आ रही हैं। देश में गुजरात टॉय मैन्यूफैक्चरिंग का हब बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल पहले मन की बात कार्यक्रम में देश के खिलौना उद्योग की जमकर तारीफ की थी।

जीवों की रक्षा के लिए CSR फंड से दिया जाए पैसा

मीरा जैन

हाल में मैं एक पशु राहत और पुनर्वास केंद्र गई, जहां हाथी, बाघ, पक्षी, सांप और दूसरे कई जीवों की देखभाल दुनिया भर के संरक्षण कार्यकर्ता कर रहे हैं। यह ऐसा काम है, जिससे हमारी संवेदनशीलता झलकती है। यह हमारे मानवीय पहलू का प्रतिबिंब है। रतन टाटा ने भी छोटे जीवों के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया है, जो CSR (Corporate Social Responsibility) का बेहतरीन उपयोग है। टाटा ग्रुप की कंपनियों के निदेशकों को इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें पशु कल्याण के लिए एफ्ँ के तहत अधिक पैसा देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि रतन टाटा भी इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

अनंत अंबानी भी पशु कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है। खुद उनके शब्दों में, 'यह पर्यावरण को दिया हुआ घाव भरने की कोशिश है।' अनंत के पिता मुकेश अंबानी ने इस बारे में गर्व से हमें बताया- उसने (अनंत ने) चार्ल्स डार्विन के 'Survival of the fittest' सिद्धांत को सिर के बल खड़ा कर दिया है और उसे 'Protection of the weakest' में बदल डाला है।

दरअसल, धरती से हर साल एक लाख करोड़ जीव गायब हो जाते हैं। 20 लाख जीवों का अस्तित्व आज खत्म होने को है। 15 करोड़ पशुओं की जान शिकार और trophy hunting के नाम पर ली जा रही है और किसी के माथे पर शिकन तक नहीं है। वहीं, हर मिनट 1.5 लाख पशु मारे जा रहे हैं। यह संवेदनहीनता हैरान करने वाली है। जीवों की हत्या को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि 36 करोड़ टन मांस से लोगों ने पेट-पूजा कर ली। यह संवेदनहीनता खत्म होनी चाहिए।

दूसरे जीवों की हत्या करने में इंसान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसकी कीमत संवेदनशील लोग और हमारी धरती चुका रही है। मानवता को तो दूसरे जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आखिर, धरती हमारा घर है तो इन जीवों का वास भी यहीं है। जब हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' कहते हैं तो उसमें यह भाव निहित होता है कि यह धरती इस पर रहने वाले सभी जीवों की है।

अगर हम जीवों की रक्षा नहीं कर पाए तो इंसानों की प्रगति का अर्थ ही क्या रह जाएगा? और क्या इस प्रगति को GDP या प्रति व्यक्ति विकास दर से मापना काफी है? क्या ये मानक वास्तविक हैं या सिर्फ एक भ्रम? CSR योजनाओं के जरिये जीवों की रक्षा पर ध्यान दिया जाए तो यह अनोखी पहल होगी। जीवों के बिना इंसानों की जिंदगी का न सिर्फ जादू कम हो जाएगा बल्कि उसका आर्थिक रूप से टिकना भी मुश्किल होगा।

एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने तीन क्रांतिकारी डेयरी सोल्यूशन्स लॉन्च किए

भारत का पहला एफटीआईआर-आधारित दूध विश्लेषक, गैस क्रोमैटोग्राफी मशीन और सोमैटिक सेल विश्लेषक लॉन्च

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

डेयरी और खाद्य परीक्षण सोल्यूशन्स में इनोवेशन के लिए विख्यात कंपनी एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने तीन क्रांतिकारी उत्पाद लॉन्च किए हैं। लॉन्च किए गए उत्पादों में भारत में पहला इऊर्ई-आधारित ध्ँ दूध विश्लेषक भी शामिल है। ध्ँ मिल्क एनालाइजर भारत में डिजाइन किया गया पहला फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (इऊर्ई) एनालाइजर है, जो कच्चे दूध की संरचना का तेजी से और सटीक विश्लेषण प्रदान करता है। यह उपकरण दूध में वसा, एसएनएफ और प्रोटीन सामग्री निर्धारित करने और केवल 30 सेकंड के भीतर सामान्य मिलावट का पता लगाने में सक्षम है। इस विश्लेषक की विशेषताओं के कारण यह ग्रामीण स्तर के दूध भंडारण और थोक दूध शीत केंद्रों में क्रांति ला देगा। इस उत्पाद को बाजार में लाने से इसका आयात भी कम करना होगा क्योंकि फिलहाल इसका ज्यादातर आयात किया जाता है।

एक अन्य प्रमुख उत्पाद मिल्क फैट फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स (एवरेस्ट जीसी4500) के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी है, जो दूध, दूध उत्पादों और घी की गुणवत्ता को मापने के लिए महत्वपूर्ण फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स की विस्तृत प्रोफाइलिंग प्रदान करता है। यह उपकरण पोषण मूल्य के सही मापन तथा ओथेन्टीसिटी के कारण डेयरी क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

वर्तमान में, फैटी एसिड विश्लेषण और ट्राइग्लिसराइड्स विश्लेषण के लिए दूध वसा के जीसी विश्लेषण के लिए अलग गैस क्रोमैटोग्राफी मशीनों का उपयोग किया जाता है। एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों का विश्लेषण करती है। इससे मशीनों, सहायक उपकरण, इंस्टॉलेशन और स्पेयर की लागत कम हो जाएगी। इन उत्पादों को हाल ही में हैदराबाद में 50वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मिनेश शाह द्वारा लॉन्च किया गया था।

एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अजीत पटेल ने कहा, 'हम दृढ़ता से मानते हैं कि इन नवाचारों में न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर डेयरी उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। ये नए लॉन्च किए गए उत्पाद वैश्विक लाभ लाएंगे और हम स्पष्ट रूप से इस सफलता को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए दूध की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में सुधार करते हुए देखते हैं। इस उपकरण का लॉन्च हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि हम डेयरी उद्योग में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।''

इस दिन मनाई जाएगी फाल्गुन पूर्णिमा

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन माह होता है। इसके बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर शुभ समय पर स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आइए, जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के किस शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करना चाहिए।

फाल्गुन पूर्णिमा स्नान और दान मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप सुबह 4.45 बजे से शाम 05 बजकर 32 मिनट बजे तक स्नान और दान कर सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को चंद्रोदय 06 बजकर 44 मिनट पर होगा। पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 25 मार्च को दोपहर 12.29 बजे समाप्त होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा।

फाल्गुन पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान

सनातन धर्म में किसी खास दिन दान करने की परंपरा चली आ रही है। दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक लोगों को वस्त्र, दक्षिणा, भोजन और अनाज समेत कई चीजें दान कर सकते हैं।

इन लोगों को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, वरना कष्टों से घिर जाएगा जीवन

हर साल होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसे में इस बार होली 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर विष्णु के महान भक्त प्रह्लाद को अग्नि से बचाया गया था। वहीं, अग्नि से न जलने का आशीर्वाद मिलने के बाद भी होलिका का दहन हो गया था।

गर्भवती महिलाएं न देखें

कई मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा या होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसका मां और बच्चे दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

नवजात शिशु पर नकारात्मक प्रभाव

गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए होलिका दहन देखना अशुभ होता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां व्याप्त हो जाती हैं। ऐसे में नवजात शिशुओं को होलिका दहन वाले स्थान से दूर रखना चाहिए।

नवविवाहिता न देखें

सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसके अनुसार, नवविवाहित महिला को अपनी सास के साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सास-बहू के एक साथ होलिका दहन देखने से उनके रिश्ता खराब होने लगता है। ऐसे में परंपरा है कि नवविवाहित महिलाएं अपनी पहली होली अपने माता-पिता के घर पर मनाती हैं।

आत्मविश्वास बढ़ाती हैं ये छोटी-छोटी बातें, सफलता के लिए हैं जरूरी

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है. हालांकि सफलता पाना आसान नहीं होता है. कई बार हमारी छोटी-छोटी कुछ आदतें ही हमारे लक्ष्य में बाधा बनती हैं. आत्मविश्वास की कमी अक्सर ही हमारे सफलता में बाधा डालने का काम करती है. आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं.

आत्मविश्वास बढ़ाती हैं ये बातें

आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको सकारात्मक मानसिकता रखनी होगी. सकारात्मक सोच आपके अंदर इस बात का भरोसा बढ़ाती है कि आप किसी से कम नहीं हैं और कोई भी काम करने में सक्षम हैं.

अपने अंदर निर्णय लेने की आदत डालें. निर्णय लेते रहने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है. कोई भी निर्णय लेते समय घबराएं नहीं. गलत निर्णय जहां आपको अनुभव देता है वहीं सही निर्णय लेने से आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है. इससे आप चुनौतियों का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर पाते हैं.

समय का ध्यान रखना. समय हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. अक्सर लोग इसे छोटी-छोटी बातों में उलझकर बर्बाद कर देते हैं. जब समय हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ निराशा मिलती है और खुद पर से भरोसा टूटने लगता है. इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाना है तो समय प्रबंधन की कला सीख लें और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें.

आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करें. एक स्पष्ट लक्ष्य आपको सही दिशा में लेकर जाता है. इससे आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है.

अपनी गलतियों पर पछतावा करने की बजाय इससे सीख लें. गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने से खुद पर भरोसा बढ़ता है. गलतियां हमेशा अनुभव देती हैं और यह अनुभव हमें सफलता की तरफ आगे लेकर जाती हैं.

जिंदगी की दौड़ में कभी भी अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. खराब सेहत की वजह से अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं और आप निराशा की तरफ बढ़ते जाते हैं. वहीं अच्छी सेहत आत्मविश्वास बढ़ाती है. इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें.

भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए खरमास में जरूर करें ये काम

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

साल 2024 में खरमास 14 मार्च से शुरू हुआ और 13 अप्रैल तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं, खरमास के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि खरमास के दौरान बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से साधक को जीवन में में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। इसके साथ ही खरमास में भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है।

भगवान विष्णु का मिलेगा आशीर्वाद

खरमास में एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है।

ॐ घृणिः सूर्याय नमः

भगवान सूर्य से जुड़ा उपाय

खरमास के दौरान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें हल्दी और गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस तरह सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खरमास के दौरान सूर्य चालीसा का पाठ करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है।

खरमास में करें ये कार्य

खरमास में जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही इस महीने अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करना चाहिए। गरीबों और बेघरों को भोजन कराएं। साथ ही कपड़ों का दान करें। इन सभी कार्यों को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है।

आमलकी एकादशी पर करें ये उपाय, बदल जाएगी किस्मत,भर जाएगी तिजोरी

श्रीमती नीतू मित्तल
8959760040
ज्योतिषाचार्य, इंदौर (म.प्र.)

20 मार्च यानी आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है. सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है. इस एकादशी में विष्णु जी के अलावा शिव-पार्वती की भी पूजा की जाती है. इस दिन किए गए कुछ उपाय विशेष फलदायी होते हैं. आमलकी एकादशी के दिन किए गए ये खास उपाय किस्मत बदल देते हैं. जानते हैं इन उपायों के बारे में.

आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है. इस दिन घर में आंवले का छोटा सा वृक्ष लगाना अति उत्तम माना जाता है. आज के दिन आंवले का पेड़ लगाने से किस्मत बदल जाती है. इस उपाय को करने से धन के भंडार भी भर जाते हैं.

आज आमलकी एकादशी के दिन 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाना शुभ माना जाता है. भगवान विष्णु को पीले फूल बेहद पसंद हैं. आज के दिन ये फूल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं.

आमलकी एकादशी के दिन आंवले का खास महत्व होता है. आज के दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल जरूर अर्पित करना चाहिए. इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. कारोबार फलता-फूलता है और करियर में तरक्की मिलती है.

आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करने से साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है. आज के दिन आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाने के बाद इसकी मिट्टी को माथे पर लगाएं. मान्यता है कि इस उपाय को करने से से कार्य में दोगुनी सफलता प्राप्त होती है. कार्यक्षेत्र की सारी समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं.

अगर पति-पत्नी के बीच कलह रहता है और हर दिन लड़ाई-झगड़े होते हैं तो आंवले के वृक्ष के तने पर सात बार सूत का धागा लपेटें. इसके बाद घी का दीपक जलाएं. माना जाता है कि इससे पति-पत्नी के संबंधों में सुधार आने लगता है.

ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भारत को बड़ा ठिकाना बनाने की तैयारी, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा ठिकाना बनाने के मकसद से सरकार ने शुक्रवार को एक नई पॉलिसी को मंजूरी दी। इसके तहत भारत में कारखाने लगाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को इंसेंटिव और टैक्स रियायतें दी जाएंगी। बड़ी शर्त यह रखी गई है कि निवेश कम से कम 4150 करोड़ रुपये का होना चाहिए और निवेश के 3 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। यह पॉलिसी टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की नजर में भारत का आकर्षण बढ़ा सकती है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया कि मिनिमम इनवेस्टमेंट 50 करोड़ डॉलर का होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पॉलिसी में कहा गया है कि कंपनी को रियायतें लेने के लिए निवेश की घोषणा के 3 साल के भीतर भारत में प्रोडक्शन शुरू करना होगा और इसके बाद तीसरे साल तक 25 पर्सेंट और पांच वर्षों में 50 पर्सेंट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का लेवल हासिल करना होगा। जो कंपनियां EV बनाने के कारखाने लगाएंगी, उन्हें कम कस्टम्स ड्यूटी पर कुछ कारें आयात करने की इजाजत भी दी जाएगी। हालांकि इंपोर्ट की जाने वाली ऐसी कारों पर कस्टम्स ड्यूटी में कुल छूट की एक सीमा होगी। यह सीमा या तो किए गए निवेश के बराबर होगी या 6484 करोड़ रुपये तक होगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 6484 करोड़ रुपये का अधिकतम इंसेंटिव दिया जाता है। मिनिस्ट्री ने बताया कि निवेश या इस रकम में जो भी कम हो, उतने के बराबर ड्यूटी छूट मिलेगी।

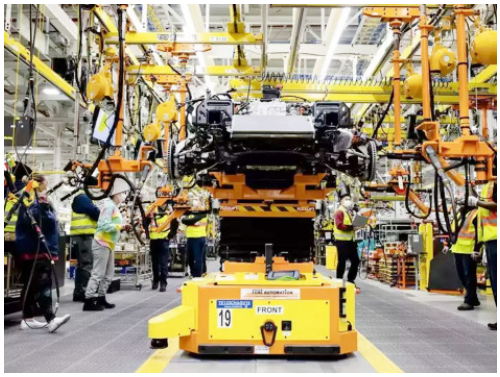

ग्लोबल कंपनियों पर है नजर

मिनिस्ट्री ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत अगर 80 करोड़ डॉलर या इससे अधिक निवेश किया गया, तो हर साल अधिकतम 8000 EV के हिसाब से अधिकतम 40 हजार EV तक के इंपोर्ट की इजाजत होगी। अगर कोई कंपनी सालाना इंपोर्ट कोटे का उपयोग नहीं कर पाएगी, तो वह इसे कैरी ओवर भी कर सकेगी। कंपनी को अगर इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट लेनी हो तो उसे इनवेस्टमेंट कमिटमेंट के सपोर्ट में बैंक गारंटी देनी होगी। अगर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और मिनिमम इनवेस्टमेंट की शर्तें पूरी नहीं की जाएंगी, तो यह बैंक गारंटी सरकार भुना लेगी। मिनिस्ट्री ने कहा कि यह पॉलिसी इस सोच के साथ बनाई गई है कि EV सेगमेंट में जानीमानी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया जा सके।

देसी कंपनियों के सामने चुनौती

इस पॉलिसी के चलते देश में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों को टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनियों से चुनौती मिलेगी। अमेरिकी कंपनी टेस्ला लंबे समय से टैरिफ कंसेशन की मांग कर रही है, जिसके जरिए 40 हजार डॉलर से कम की कारों पर कस्टम्स ड्यूटी 70 प्रतिशत तक कम की जाए और इससे ज्यादा दाम की कारों पर पूरी ड्यूटी माफ कर दी जाए। उसने भारत में कारखाना लगाने के लिए यह शर्त रखी थी। हालांकि पिछले दिनों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ किया था कि भारत विदेशी कंपनियों के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाएगा और यहां के कानून और टैरिफ रूल्स ऐसे होंगे, जो दुनियाभर की EV कंपनियों को आकर्षित करें।

मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

यह पॉलिसी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। नई के मामले में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को लेटेस्ट टेक्नॉलजी मिलेगी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इसकी कॉस्ट घटेगी। नई का उपयोग बढ़ने पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम होगी। प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। ध्यान केवल यह रखना होगा कि ग्लोबल कंपनियों के सामने देसी कंपनियों को उचित नीतिगत सहयोग भी मिले।

20 महीने के टॉप पर पहुंचा एक्सपोर्ट, आखिर भारत से क्या मंगा रहे अमेरिका, यूएई और सिंगापुर?

नई दिल्ली। एजेंसी

एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है। फरवरी में देश का निर्यात 20 महीने के टॉप पर पहुंच गया है। इस दौरान अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात में उछाल के कारण एक्सपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार तीसरे महीने भारत से एक्सपोर्ट में तेजी आई है। फरवरी में अमेरिका को एक्सपोर्ट 22 फीसदी तेजी के साथ 7.2 अरब डॉलर पहुंच गया। इसी तरह यूएई को एक्सपोर्ट में 23.1 फीसदी तेजी आई है जबकि सिंगापुर को निर्यात में 51.6 फीसदी की तेजी आई है। साउथ अफ्रीका के लिए एक्सपोर्ट फरवरी में 100 फीसदी बढ़ गया। हालांकि इस दौरान हॉन्ग कॉन्ग को एक्सपोर्ट में 27.9 फीसदी की गिरावट आई है।

मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स की लिस्ट में स्मार्टफोन सबसे ऊपर हैं। जनवरी में भारत से 53 करोड़ डॉलर के स्मार्टफोन अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए। पिछले साल के मुकाबले इसमें 79 फीसदी तेजी आई है। इसके साथ ही भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले आइडटम्स की लिस्ट में पॉलिश्ड डायमंड दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इस दौरान भारत से अमेरिका को 38 करोड़ डॉलर के पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट किए गए।

फाइनेंशियल ईयर 2024 के अप्रैल से जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को 4.1 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए जबकि यूएई को 2.2 अरब डॉलर का शिपमेंट भेजा गया। फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्यात में 54.8 फीसदी की तेजी आई।

भारत से क्या हो रहा एक्सपोर्ट

फरवरी में यूएई को एक्सपोर्ट 23.1 फीसदी बढ़कर 3.5 अरब डॉलर पहुंच गया। अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यूएई को 31.7 करोड़ डॉलर का गोल्ड, 23.7 करोड़ डॉलर के स्मार्टफोन और 24.3 करोड़ डॉलर का मोटर गैसोलीन एक्सपोर्ट किया गया। इसी तरह सिंगापुर को एक्सपोर्ट फरवरी में 51.6 परसेंट बढ़ गया। इस देश को पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के एक्सपोर्ट में 280 फीसदी तेजी आई है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका को एक्सपोर्ट दोगुना होकर 1.16 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-जनवरी के आंकड़े देखें तो भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में यह देश 16वें से उछलकर 10वें नंबर पर आ गया है। दक्षिण अफ्रीका को एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स में पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स सबसे आगे है।

अप्रैल से सितंबर तक देश से पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के एक्सपोर्ट में गिरावट आई थी। लेकिन अक्टूबर से इसमें लगातार तेजी दिख रही है। जनवरी में भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के एक्सपोर्ट में 89 फीसदी तेजी आई और यह 21.9 करोड़ डॉलर पहुंच गया। फरवरी में भारत से सऊदी अरब को एक्सपोर्ट में 50 फीसदी तेजी आई। इसी तरह नीदरलैंड को एक्सपोर्ट 26.7 फीसदी, यूके को 31.9 फीसदी, बांग्लादेश को 18.1 फीसदी और चीन को 13.3 फीसदी बढ़ गया। हालांकि हॉन्ग कॉन्ग को एक्सपोर्ट में 27.9 फीसदी की गिरावट आई।

पथ्य 2030 कौशल लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है आईएचसीएल

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसीएल) सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक प्रभाव उपायों की अपनी पहल पथ्य के तहत काम करते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्ष 2030 तक 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आईएचसीएल भारत के 15 राज्यों के 25 शहरों में 32 कौशल केन्द्रों का या तो संचालन कर रही है या फिर उनके साथ सहभागिता में है।

इस अवसर पर आईएचसीएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष-मानव संसाधन श्री गौरव पोखरियाल ने कहा, ''हमारे संस्थापक जमशेदजी टाटा की दूरदर्शिता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आईएचसीएल का प्रयास ऐसी नीतियों व कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का है जिनसे एक मानवोचित एवं समावेशी समाज हेतु आवश्यक पुलों का निर्माण जारी रहे। हाशिए पर रहने वाले योग्य युवाओं को रोजगार के काबिल की राह में जो चुनौतियां उनका समाधान करने के लिए हम समर्पित हैं। इन भागीदारियों द्वारा क्षमता निर्माण से व्यापक अप्रत्यक्ष असर कायम होगा, खासकर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और आदिवासी समूहों के लिए।''

राज्य सरकारों, संस्थानों व निजी संगठनों के साथ साझेदारी कर के आईएचसीएल ऐसे हस्तक्षेप करती है जिनमें व्यापारिक मजबूती होती है, जिससे की वंचित वर्ग के युवाओं की रोजगार पाने की काबिलियत में इजाफा होता है। आईएचसीएल की नॉलेज पार्टनरशिप में शामिल हैं- प्रशिक्षण सामग्री, कक्षाओं की रचना पर सुझाव, फैकल्टी विकास, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, संयुक्त प्रमाणन तथा हमारे इंडस्ट्री नेटवर्क के जरिए अन्य सहयोग।

तेजी से बढ़ते हॉस्पिटैलिटी उद्योग में वंचित युवाओं को रोजगार हेतु कुशल बनाने के लिए आईएचसीएल पूरे भारत में कौशल केन्द्रों के साथ साझेदारी करती है और अब तक कंपनी 10,000 कुशल युवाओं में से 75 प्रतिशत युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार दिलवा चुकी है। ये कौशल केन्द्र चमोली, उत्तराखंड; छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश; देबारी, राजस्थान; पोंडा, गोवा; ऐरोली, महाराष्ट्र; कुकटपल्ली, आंध्र प्रदेश और एकता नगर, गुजरात जैसी जगहों पर स्थित हैं।

इंडियन होटल्स कंपनी को भारतीय आतिथ्य का संरक्षक माना जाता है और यह कंपनी उद्योग के लिए योग्य प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने हेतु निरंतर निवेश कर रही है। कंपनी का उद्देश्य है लायक युवाओं व उनके परिवारों को विकसित करना व सहयोग देना और साथ ही इस उद्योग की समग्र प्रगति में भी योगदान करना।

चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एचएमडी निरंतर अग्रसर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डिस्पोजेबल और ऑटोडिसेबल सिरिंज बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी हिन्दुस्तान सिरिंजिस एंड मेडिकल डिवाइसिस (HMD) ने सबसे उन्नत व अपनी तरह का पहला डिस्पोजेक्ट सिंगल यूज़ सिरिंज, सेफ्टी नीडल के साथ इंदौर में लांच किया है। यह उत्पाद चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर तथा वैश्विक शक्ति बनाने में मददगार साबित होगा। एचएमडी (HMD) आने वाले दिनों में देशभर में डिस्पोजेक्ट लॉन्च करेगा।

भारत चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए आत्मनिर्भर केन्द्र बनने हेतु प्रयासरत है और यह लांच इसी दिशा में देश को मजबूत करेगा। अपेक्षा है कि डिस्पोजेक्ट स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाली चोटों व उनसे जुड़ी लागत को कम करते हुए स्वास्थ्य उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव कायम करेगा।

एचएमडी का लक्ष्य है क्रांतिकारी डिस्पोजेक्ट सेफ्टी सिरिंज के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों को पेश आने वाली नीडल स्टिक इंजरी से बचाना, संक्रमण नियंत्रण की लागत घटाना और स्वास्थ्य उद्योग पर दीर्घकालिक सकारात्मक वित्तीय प्रभाव कायम करना। देश में निर्मित तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद भारत को अनुसंधान एवं विकास के मोर्चे पर मजबूती प्रदान करेंगे। इस प्रकार भारतीय कंपनियां इस काबिल बनेंगी की वे चोट से बचाने वाली सिरिंजों की मांग पूरी कर सकें जिनकी विश्व बाजार में बहुत जरूरत है।

एचएमडी के प्रबंध निदेशक श्री राजीव नाथ ने कहा, ''सेफ्टी शील्ड (एसआईपी शील्ड) से युक्त डिस्पोजेक्ट सिरिंज नीडल स्टिक इंजरी की चिंताओं का समाधान करती है और हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है कि बतौर मार्केट लीडर हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु निरंतर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल का यह बहुत ही बढ़िया परिणाम है और इसके जरिए हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे।'' उन्होंने यह भी कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भरता के जज़्बे के साथ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण एवं निर्यात का वैश्विक पावरहाउस बनने के लिए तैयार है।

TK Elevator विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था के साथ नई उपलब्धियाँ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मशहूर जर्मन मल्टीनेशनल एलिवेटर कंपनी, TK Elevator भारत में मोबिलिटी बाजार की डायनामिक्स को पहचानकर इस उद्योग में लगातार इनोवेशन और वृद्धि लेकर आ रही है।

कमर्शियल, रिटेल, सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैल्थकेयर, हॉस्पिटलिटी, एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में लंबे सहयोग के साथ कंपनी की वृद्धि से स्थानीय बाजार की ओर इसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। भारत की तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था में विलासितापूर्ण आवासीय घरों और विला की मांग बढ़ रही है, जिससे TK Elevator को इस बाजार में विकास करने के और ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। भारत के विकसित होते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सेवाएं देने की इसकी अडिग प्रतिबद्धता के साथ 2017 में चाकन, पुणे में TK Elevator की अत्याधुनिक आरएंडडी एवं मैनुफैक्चरिंग सुविधा

का उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान के साथ TK Elevator के कई इनोवेटिव एवं टेक-आधारित उत्पादों का निर्माण स्थानीय स्तर पर स्वदेशी रूप से किया जाता है, ताकि वो स्थानीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल होकर उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। TK Elevator भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में विभिन्न सेक्टरों में मौजूद है, जिससे देश में प्राथमिक मोबिलिटी सॉल्यूशन पार्टनर्स में से एक के रूप में इसकी सफलता प्रदर्शित होती है। मुख्य कन्वेंशन सेंटर्स, जैसे आईआईसीसी (यशोभूमि) और आईईसीसी (भारत मंडपम), जहाँ नई दिल्ली में जी20 समिट का आयोजन हुआ, के साथ साझेदारी करने से लेकर हैदराबाद में एसएएस आईटॉवर, मैराथन फ्यूचर एक्स और मुंबई में रुपारेल एरियाना जैसे हाई-राईज़ और हाई-स्पीड प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देने तक TK Elevator के उत्पाद भारत के सबसे बड़े शहरों में और अनेक टाउनशिप्स में स्थापित किये चुके है, जिनमें बैंगलुरू में भारतीय सिटी, गुड़गाँव में वाटिका, और पुणे में अमानोरा पार्क टाउन शामिल हैं। इसके अलावा, TK Elevator देश के सबसे बड़े मॉल डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, जैसे आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में अस्पतालों जैसे सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल, और बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DIAL), बैंगलुरू, कोच्चि, पुणे, गुवाहाटी, और नोएडा एयरपोर्ट्स, और कोलकाता एवं पुणे मेट्रो में भी मौजूद है।

रियलमी ने पेश किया रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में सबसे विश्वसनीय स्मार्टफोन सेवा प्रदाता, रियलमी ने अपने अपनी नार्जो सीरीज में नया स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी पेश किया है। रियलमी की नार्जो सीरीज में यूजर्स को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन की एक स्टाइलिश श्रृंखला आती है। भारत में लगातार बढ़ते हुए 16 मिलियन यूजर्स के साथ रियलमी की नार्जो सीरीज अगली पीढ़ी के स्मार्टफोन पेश करती है। इन डिवाइसेज को आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ डिजाइन

किया गया है ताकि यूजर्स शिखर पर रहते हुए अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सकें। नए रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी का उद्देश्य लो-लाइट फोटोग्राफी में नए मानक स्थापित करना और इनोवेशन एवं उत्कृष्टता की रियलमी की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। इस लॉन्च के बारे में रियलमी के प्रवक्ता ने कहा आज हम केवल अमेजन पर रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी पेश करके उत्साहित हैं यह एक ऐसा स्मार्टफोन है जो स्मार्टफोन उद्योग में लो-लाइट फोटोग्राफी के मानकों को बदल देगा। रियलमी का नार्जो सीमाओं को आगे बढ़ाने और ऐसे उत्पाद पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो युवा और तकनीक-प्रेमी ग्राहकों की रुचि के अनुरूप है। रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी के साथ हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स पेश किए हैं, जो मिड-रेंज सेगमेंट को फिर से परिभाषित करेंगे। हमारा मानना है कि यह स्मार्टफोन एक इनोवेटिव और ट्रेंड-सेटिंग स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में हमारी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना देगा।'

पैसे न हों तो भी मिलेगा इस स्टेशन पर टिकट, भारतीय रेलवे ने शुरू की नई व्यवस्था

नई दिल्ली। एजेंसी

कभी-कभी आप ट्रेन से सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और टिकट लेने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो पता चलता है कि आप पर्स या फिर पैसे रखना भूल गए। इन हालातों में आपके सामने बड़ी समस्या आती है कि अब क्या होगा. सफर कैसे पूरा किया जाएगा? भारतीय रेलवे ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत यात्री की जेब में पैसे नहीं होने के बाद भी ट्रेन से सफर कर सकेगा।

रेलवे ने डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए आगरा मंडल ने आगरा छावनी स्टेशन पर यह खास सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, तो भी सफर के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर कैश लेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से अनारक्षित टिकट व प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान की गयी है। यह सुविधा एक स्पेशल कैश लेस काउंटर के माध्यम से दी जा रही है, जहां क्यूआर कोड स्कैनर के साथ फेयर डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें यात्री अपना किराया स्क्रीन पर देख सकते हैं एवं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते है, जो रेलवे एवं यात्रियों के मध्य पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

सिर्फ यही नहीं, आगरा मंडल के सभी स्टेशनों (आगरा छावनी ,आगरा किला, मथुरा जं. इत्यादि) में खानपान की सामग्री खरीदकर क्यूआर कोड के माध्यम से कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग सुविधा का भुगतान भी क्यूआर कोड के माध्यम से कैशलेस तरीके से किया जा सकता है। यदि यात्री पे एंड यूज़ शौचालय का उपयोग करते हैं तो इसका भुगतान भी कैश लेस पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। कैश लेस पेमेंट से यात्रियों के समय की बचत होगी और खुले पैसों का झंझट भी नहीं रहेगा। स्मार्ट फ़ोन की बढ़ती उपलब्धता के साथ ही क्यूआर कोड / यूपीआई पेमेंट सभी के लिए सुलभ और आसान हो गया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।